

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२२५)-०२-०६/२०२६- 324

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
दीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-०१ अनुसूचित जातियों का कल्याण-१९०-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, ०००१-बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम" विपत्र कोड ४४-२२२५०११९००००१" (मॉग संख्या ४४) के अन्तर्गत ३१०४-सहायक अनुदान-वेतन में कुल ₹४४२.०० लाख (चार करोड़ बियालीस लाख ₹०) के उपबंधित राशि में संग्रहित बचत राशि से "मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-०१ अनुसूचित जातियों का कल्याण-००१-निर्देशन और प्रशासन,०००१-निर्देशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड-४४-२२२५०१००१०००१" (मॉग संख्या-४४) के अन्तर्गत २८०२-संविदा सेवायें ईकाई में कुल ₹२१.०० लाख (एककीस लाख ₹०)(एककीस लाख ₹०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव।

आदेश- स्वीकृत।


२- बिहार वित्तीय नियमावली भाग १ के नियम ४८९ योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-०१ अनुसूचित जातियों का कल्याण-००१- निर्देशन और प्रशासन, ०००१-निर्देशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- ४४-२२२५०१००१०००१" (मॉग संख्या-४४) के अन्तर्गत २८०२-संविदा सेवायें ईकाई में कुल ₹२१.०० लाख (एककीस लाख ₹०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

३- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।


४- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

५- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे।

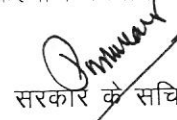
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


०६-०३-२६
सरकार के सचिव

ज्ञापक- संसं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२२५)-०२-०६/२०२६-३२४ पटना,दिनांक- १०/०३/२०२६
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


०६-०३-२६
सरकार के सचिव

ज्ञापक- संसं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२२५)-०२-०६/२०२६-३२४ पटना,दिनांक- १०/०३/२०२६
प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ कोषागार पदाधिकारी, सिंवाई भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक(गु०) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रभाषी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (८डी०)/लेखा शाखा/आईटी०मैनेजर, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


०६-०३-२६
सरकार के सचिव



अतिरिक्त/अनुदान
के लिए आवेदन-पत्र।
पुनर्विनियोग

ज़ांप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001- निदेशन और प्रशासन, 0001-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- 44-2225010010001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2802-संविदा सेवायें ईकाई में कुल ₹21.00 लाख (एक्कीस लाख रू०) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु
.....के क्रम में

स्वीकृति के लिए


को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान
की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।
प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्यय
पदाधिकारी का पदनाम -प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला
कल्याण पदाधिकारी।

अतिरिक्त/अनुदान
की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में
स्पष्टीकरण

पुनर्विनियोग यदि कुछ हो- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष ज़ांप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, 0001-बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम" विपत्र कोड- 44-2225011900001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 3104-सहायक अनुदान- वेतन में कुल ₹442.00 लाख (चार करोड़ बियालीस लाख रू०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से "मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001- निदेशन और प्रशासन, 0001-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड-44-2225010010001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2802-संविदा सेवायें ईकाई में कुल ₹21.00 लाख (एक्कीस लाख रू०) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।


स्वीकृत
अनु. पुनर्विनियोग एवं अनुदान प्रशासिका
कल्याण विभाग, बिहार, पटना

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

ग्रहण शीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग कल्याण-01-निदेशन और प्रशासन, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग उपशीर्ष-0001-निदेशन एवं प्रशासन (विपत्र कोड 44-2225010010001) विकास निगम, पटना (विपत्र कोड 44-2225011900001)

20309

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है (44-2225010010001)

शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है (44-2225011900001)

विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	प्रत्यपित राशि।	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0
0001,2802-संविदा सेवायें	51000000	51000000	53100000	2100000	53100000	3104-सहायक अनुदान- वेतन	44200000	36200000	34100000 कुल-	21000000 (एककीस लाख रुपये)	34100000

साक्षि - 20-01-24
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना

टिप्पणी- (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखायें जायें, जिनसे इकाई संबंधित हो। अन्य इकाइयों पुनर्विनियोजित

रकम को घटाकर, दिखाई जाय।
(ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार
(ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।
(घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।
(ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा पीठ पीठ पर दिया जाय।